



आरत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, शुक्रवार, १० फरवरी १९७८/माघ २१, १८९९
No. 70] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 1978/MAGHA 21, 1899

इस भाग में अलग संख्या वी आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रीमण्डल सचिवालय

मध्यस्थिति

नई दिल्ली, १० फरवरी, १९७८

का० आ० ४४(भ)—राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद ७७ के खण्ड (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, १९६१ में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रथमतः—

१. (१) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सी पक्षीमत्ता संबोधन) नियम, १९७८ है।

(२) ये तुरन्त प्रकृत होंगे।

२. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, १९६१, (जिसे इसमें इसके पक्षीमत्ता उक्त नियम कहा गया है) में प्रथम अनुसूची में,—

(क) १क, १ब और १ग प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जायेगी, प्रथमतः—

“१क. वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय :

(i) वाणिज्य विभाग ;

(ii) नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग ।”;

(ब) प्रविष्टि १५ के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रविष्टि रखी जायेगी प्रथमतः—

“१५. पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय :

(i) पैट्रोलियम विभाग ।

(ii) रसायन और उर्वरक विभाग ।”;

३. उक्त नियमों की दिनांक अनुसूची में,—

(क) शीर्षक “रसायन और उर्वरक मंत्रालय”, तथा उसके अन्तर्गत प्रविष्टिया हटा दी जायेगी ;

(ब) शीर्षक “नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय”, तथा उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों को हटा दिया जायेगा ;

(ग) शीर्षक “वाणिज्य मंत्रालय”, तथा उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टिया रखी जायेगी, प्रथमतः—

“वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय ”

क. वाणिज्य विभाग

I. कामालय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सीति

१. अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य सीति ।

२. वाणिज्य सीति से मुक्ततः सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण जैसे यू०८०सी०टी०।०डी०, ई०सी०८०एफ०५०, ई०सी०४०, ई०सी०अ०५०, ई०५०सी०१०, ई०५०फ०टी०५०, जी०५०टी०टी० ।

३. गेहूं से संबंधित करारों से निम्न अन्तर्राष्ट्रीय वस्तुकरार ।

४. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सीति से संबंधित अन्य विषय जिनमें हैरिक और टैरिफ-हतार प्रबोध सम्मिलित हैं ।

II. विदेश व्यापार

5. विदेश व्यापार से संबंधित सभी विषय जिनमें व्यापार बातों, और कारार (जिनमें ईरिक और व्यापार विषयक साधारण कारार और राज्यमंडल ईरिक प्रधिनियम सम्मिलित है), व्यापार मिशन और प्रतिनिधिमंडल, व्यापार महायोग और नवंदेश, और विदेशस्थ मार्सीय व्यापारियों के हितों को भरतीय मिशनित है।

6. आयात और निर्यात व्यापार नीति और नियंत्रण जिसमें निम्नसिद्धित विषय सम्मिलित नहीं है :—

- (i) कथा चिन्हों का आयात;
- (ii) भारतीय फिल्मों वा निर्माण—दीर्घ और लघु कथा चिन्ह दोनों; और
- (iii) चलचित्र (अनुद्भासित) और फिल्म उद्योग द्वारा प्रोत्साहित प्रत्य वस्तुओं का आयात और वितरण।

7. मुख्य नियंत्रक, आयात और नियात।

III. राज्य व्यापार

8. राज्य व्यापार की नीतियों और इस प्रयोजन के लिये स्थापित संगठनों का कार्य, जिसमें ये आते हैं :—

- (i) राज्य व्यापार निगम और उसकी निम्नतिवित महायक मंस्ताएँ :—
 - (क) भारतीय काजू निगम;
 - (ख) भारतीय परियोजना और उपस्कर निगम।
- (ii) अनिज और धारु व्यापार निगम।

शहु के साथ व्यापार, शहु सम्पत्ति

9. शहु के साथ व्यापार, शहु कर्म और शहु सम्पत्ति; हासि-पूर्ति (जर्मत औषधीयिक उपस्कर में जिस), शहु-व्यापार नियंत्रक, शहु कर्म नियंत्रक; भारत के लिये शहु सम्पत्ति-प्रभिन्नक।

10. ईरिक आयोग [ईरिक आयोग प्रधिनियम, 1951 (1951 का 50)] उद्योगों को ईरिक सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-वस्तुक ईरिक-व्यूरो।

11. सभी वस्तुओं, उत्पादों, नियन्त्रियों और प्रधं निम्नियों, जिनमें निम्नतिवित सम्मिलित हैं, से संबंधित नियात उत्पादन का विकास और विस्तार :

- (क) कृषि उत्पाद (छेणीकरण और अंकन) प्रधिनियम, 1937 के अन्तर्गत आने वाली कृषि उपज;
- (ख) समुद्री उत्पाद;
- (ग) औषधीयिक उत्पाद (इंजीनियरी का सामाज, कैमिकल्स, प्लास्टिक, चमड़ा उत्पाद, आदि);
- (घ) ईंधन, अनिज और अनिज उत्पाद;
- (ङ) विनिर्दिष्ट नियातोन्मुख उत्पाद (जिनमें बागान उपज आदि तो आते हैं जेकिन पटसन अत्याव और हस्तशिल्प नहीं आते) जो प्रत्यक्षत इस विभाग के भारसाधन में हैं;
- (च) वस्त्र, उन्नी वस्त्र, हथकरघा वस्त्र, रेखमी और सेलुलोसी तन्तु, पटसन और पटसन उत्पाद, और हस्तशिल्प।

12. वे सभी संगठन और संस्थाएँ जो निर्वात उद्यम से संबंधित सेवाओं की व्यवस्था से सम्बद्ध हैं जिनमें निम्नतिवित सम्मिलित है :—

- (क) नियात साज और प्रत्याखूति निगम।
- (ख) नियात निरीकण परिषद्।
- (ग) वाणिज्यिक भासूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय।
- (घ) प्रवर्गनी और वाणिज्य भारत निदेशालय
- (ङ) निःशुल्क व्यापार जोग।

13. नियात उद्यम के लिये प्रोत्साहक और सहायक परियोजनाएँ और कार्यक्रम।

14. आयात उपज, आय, काफी, रबड़, और इलायची का उत्पादन, वितरण (देश में व्यापत और नियात के लिये) और विकास।

15. (i) भारतीय चाय व्यापार निगम।

(ii) चाय बीड़।

(iii) काफी बोड़।

(iv) रबड़ बोड़।

(v) इलायची बोड़।

(vi) हस्तशिल्प और हथकरघा-वस्त्र नियात निगम।

वे नियातिक वृत्ति और सहकारिता विभाग

I. आन्तरिक व्यापार

1. आन्तरिक व्यापार।

2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, स्पर्ट-युक्त नियमितियां अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण प्रधिनियम, 1955।

3. बागदा बाजार का नियंत्रण [प्रथम मंविदा (विनियमन) प्रधिनियम, 1952]।

4. आवश्यक वस्तु प्रधिनियम, 1955 (ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रवाय, भीमते और वितरण, जो विनिर्दिष्ट, किसी अन्य मत्रालय द्वारा व्यवहृत नहीं है)।

II. व्यापार विहृ भावि

5. व्यापार और वाणिज्य विहृ न प्रधिनियम, 1958।

6. संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) प्रधिनियम, 1950।

7. बाट और माप मानक (बाट और माप मानक प्रधिनियम, 1956—बाट और माप मानक प्रधिनियम, 1976)।

8. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी मंस्तान या प्रधीनस्त कारोबार या प्रत्य संगठन, जिनमें फारवर्ड मार्केट्स कमीशन, बस्कर्व भी मिशनित हैं।

III. सहकारिता

9. सभी सेक्टरों में सहकारिता और सहकारी क्रियाकलापों के समन्वय के क्षेत्र में साधारण नीति (संबंधित मकालय प्रभने-भीमते क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के लिये उत्तरवायी है)।

10. राष्ट्रीय सहकारी संगठनों से पर्याप्ति नाम।

11. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।

12. ऐसी सहकारी सोसाइटियों का, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, निगमन, विनियमन और परिसमाप्ति।

13. सहकारी विभागों और सहकारी संस्थाओं के कार्यक्रमों का प्रशिक्षण (जिनमें सरस्यों, पश्चात्याकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों की शिक्षा सम्मिलित है)।

14. उपभोक्ता सहकारी संस्थाएँ।

15. लोक विसरण प्रणाली।

16. कोमतो का परिवीक्षण और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता।

17. राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्।

18. पैक की दुर्ई वस्तुओं का विनियमन।

19. कानूनी माप-विद्या में प्रशिक्षण।

20. भारतीय मानक मस्ता (प्रमाणन विहृन) प्रधिनियम, 1952।

21. वे उद्योग, जिनके लिये संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का विभवण लोकहित में समीक्षीय है, जहां तक

- वे बनस्पति धी, तिलहन, बनस्पति तेलों, खाली और वमा से सम्बद्ध हैं।
22. बनस्पति धी, तिलहन, बनस्पति तेलों, खाली और वमा का प्रत्यारूपित व्यापार और आणिज्य, उनका मूल्य-नियन्त्रण, पूर्ति और वितरण।
23. बनस्पति धी, बनस्पति तेल और वमा निदेशालय।”;
- (ब) शोषक “पेट्रोलियम मंत्रालय”, और उसके प्रत्यारूप आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियों रखी जाएँगी, अर्थात्—
- “पेट्रोलियम, रमायन और उर्वरक मंत्रालय”

क. पेट्रोलियम विभाग

1. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन, प्रदाय, वितरण और कीमतें।
2. भारत में तेल के माध्यनकों के लिए खोज और उनका शोषण, जिसके प्रत्यारूप भागदाही परियोजनाओं, उदाहरणार्थ हँड़-स्टैनबैक पेट्रोलियम प्रोजेक्ट, आयस इंडिया लिमिटेड आदि की स्थापना भी है।
3. भारत में तेल परिकरणियों की स्थापना।
4. निम्नलिखित द्वारा परिकरणी उत्पादों का उत्पादन—
 - (i) स्टेनडर्ड बैंकुअम रिफाइनरी कम्पनी, अम्बई;
 - (ii) बम-गोल रिफाइनरी, अम्बई;
 - (iii) कालटेस रिफाइनरी, विशाखापत्तनम; तथा
 - (iv) असम आयल कम्पनी लिमिटेड, दिग्बोरी।
5. स्नेहक तेल संयन्त्रों की स्थापना।
6. पेट्रो-रसायन।
7. सेलुलोसरहित संश्लिष्ट फाइबर (नायनान, टेमीलीन, पोलिमे-स्टर, प्रक्रियिक धाति के उत्पादन से संबंधित उत्पाद।
8. संश्लिष्ट रबड़।
9. प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिकों की विरचना और प्लास्टिक की छली हुई वस्तुएँ शामिल हैं।
10. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम-उत्पादों के वित्रय के लिए वितरक संगठन की स्थापना।
11. विभाग द्वारा अवाहृत सब उत्पादों की योजना, विकास तथा नियन्त्रण और महायता।
12. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन, ऐसी परियोजनाओं के मिशन, जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्ट प्रावंटित हैं, इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के प्रत्यंगत आने वाली प्रक्रियक सेक्टर परियोजनाएँ।;

क्ष. रसायन और उर्वरक विभाग

1. उर्वरक।
2. औषधियों तथा प्रन्त्य सूखम रमायन।
3. कार्सिक सोडा और सोडा ऐश।
4. क्लोरीन।
5. सल्फूरिक एसिड।
6. कीटनाशी (कीटनाशी प्रधिनियम, 1968 के प्रणालन के प्रतिरक्त)।
7. ऐटिकार्योटिक्स।
8. पावल ऐल्कोहोल।
9. पेय ऐल्कोहोल।

10. ऊपरा उपचार लवण।
11. रंजक द्रव्य।
12. कार्बनिक और प्रकार्बनिक भारी रसायन।
13. प्रकार्बनिक रसायन, प्रथात् वे रसायन जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतया प्रावंटित नहीं किए गए हैं।
14. विभाग से संबंधित सभी उद्योगों का आयोजन, विकास और नियन्त्रण तथा उन्हें सहायता।
15. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी संलग्न प्रथवा अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन।
16. पायराइट्स, फासफेट्स एंड केमिकल्स लिंग।
17. इस सूची में सम्मिलित विषयों के प्रत्यंगत आने वाली प्रन्त्य सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएँ, जिनमें वे परियोजनाएँ नहीं हैं जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतया प्रावंटित की गई हैं।

नीलम मंजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/78-सी० एफ०]

आदल गय, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 1978

S.O. 88(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and twenty-fifth Amendment) Rules, 1978.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 (hereinafter referred to as the said rules), in the First Schedule,—
 - (a) for entries 1A, 1B and 1C the following entry shall be substituted, namely :—

“1A. Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Vanijya, Nagrik Poorti aur Sahkarita Mantralaya) :

 - (i) Department of Commerce (Vanijya Vibhag).
 - (ii) Department of Civil Supplies and Cooperation (Nagrik Poorti aur Sahkarita Vibhag).”;
 - (b) for entry 15, the following entry shall be substituted, namely :—

“15. Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Petroleum, Rasayan aur Urvarak Mantralaya) :

 - (i) Department of Petroleum (Petroleum Vibhag).
 - (ii) Department of Chemicals and Fertilizers (Rasayan aur Urvarak Vibhag).”;
3. In the Second Schedule to the said rules,—
 - (a) the heading “MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)”, and the entries thereunder shall be omitted;
 - (b) the heading “MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (NAGRIK POORTI AUR SAHKARITA MANTRALAYA)”, and the entries thereunder shall be omitted;
 - (c) for the heading “MINISTRY OF COMMERCE (VANIJYA MANTRALAYA)” and the entries

thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (VANIJYA, NAGRIK POORTI AUR SAHKARITA MANTRAI ATMA)".

**A. DEPARTMENT OF COMMERCE
(VANIJYA VIBHAG)**

I. General International Trade Policy

1. International Commercial Policy.
2. International agencies principally connected with commercial policy (e.g. UNCTAD, ECAFE, ECA, ECIA, EEC, EFTA, GATT).
3. International commodity Agreements other than agreements relating to Wheat.
4. All matters relating to international trade policy including tariff and non-tariff barriers.

II. Foreign Trade

5. All matters relating to foreign trade including trade negotiations, and agreements (including General Agreements on Tariffs and Trade and Commonwealth Tariff Preferences), trade missions and delegations, trade cooperation and promotion, and protection of interests of Indian traders abroad.

6. Import and Export Trade Policy and Control excluding the matters relating to—

- (i) import of feature films;
- (ii) export of Indian films—both feature length and shorts; and
- (iii) import and distribution of cine-film (un-exposed) and other goods required by the film industry.

7. Chief Controller of Imports and Exports.

III. State Trading

8. Policies of State Trading and performance of organisations established for the purpose, including :

- (i) State Trading Corporation and its following subsidiaries :—
 - (a) Cashew Corporation of India;
 - (b) Projects & Equipment Corporation of India.
- (ii) Minerals & Metals Trading Corporation.

IV. Trading with the enemy, enemy property

9. Trading with the enemy, enemy firms and enemy property ; reparations (other than German industrial equipment); Controller of Enemy Trading ; Controller of Enemy firms ; Custodian of Enemy Property for India.

10. Tariff Commission [The Tariff Commission Act, 1951 (50 of 1951)], Tariff Protection to Industries, International Customs Tariff Bureau.

11. Development and expansion of export production in relation to all commodities, products, manufactures, and semi-manufacturers including the following :

- (a) agricultural produce within the meaning of the Agricultural produce (Grading and Marking) Act, 1937;
- (b) marine products;
- (c) industrial products (engineering goods, chemicals, plastics, leather products, etc.);
- (d) fuels, minerals and mineral products;
- (e) specific export-oriented products (including plantation crops etc. but excluding jute products and handicrafts) which are directly the charge of this Department.
- (f) textiles, woollens, handlooms, readymade garments, silk and cellulosic fibres, jute and jute products, and handicrafts.

12. All organisations and institutions connected with the provision of services relating to the export effort including :

- (a) Export Credit and Guarantee Corporation.
- (b) Export Inspection Council.
- (c) Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.
- (d) Directorate of Exhibitions and Commercial Publicity.
- (e) Free Trade-Zones.

13. Projects and Programmes for stimulating and assisting the export efforts.

14. Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of plantation crops, tea, coffee, rubber and Cardamom.

15. (i) Tea Trading Corporation of India.

- (ii) Tea Board
- (iii) Coffee Board.
- (iv) Rubber Board.
- (v) Cardamom Board.
- (vi) Handicrafts and Handlooms Export Corporation.

B. DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (NAGRIK POORTI AUR SAHKARITA VIBHAG)

I. Internal Trade

1. Internal Trade.

2. Inter-State Trade ; the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955.

3. Control of futures trading [The Forward Contracts (Regulation) Act, 1952].

4. The Essential Commodities Act, 1955 (Supply, prices and distribution of essential commodities not dealt with specifically by any other Ministry).

II. Trade Marks etc.

5. The Trade and Merchandise Marks Act, 1958.

6. The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.

7. Standards of Weights and Measures (The Standards of Weights and Measures Act, 1956—The Standards of Weights and Measures Act, 1976).

8. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, including the Forward Markets Commission, Bombay.

III. Co-operation

9. General policy in the field of Co-operation and co-ordination of co-operation activities in all sectors (The Ministries concerned are responsible for Co-operatives in their respective fields).

10. Matters relating to National Co-operative Organisations.

11. National Co-operative Development Corporation.

12. Incorporation, regulation and winding up of co-operative societies with objects not confined to one State.

13. Training of personnel of co-operative departments and co-operative institutions (including education of members, office bearers and non-officials).

14. Consumer Co-operatives.

15. Public Distribution System.

16. Monitoring of prices and availability of essential commodities.

17. The National Consumer Protection Council.

18. Regulation of packaged commodities.
19. Training in legal Metrology.
20. The Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952.

21. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest, as far as these relate to Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.

22. Price control of and inter-state trade and commerce in and supply and distribution of Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.

23. Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats.”;

(d) for the heading “MINISTRY OF PETROLEUM (PETROLEUM MANTRALAYA)”, and the entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

“MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (PETROLEUM, RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA).”

**A. DEPARTMENT OF PETROLEUM
(PETROLEUM VIBHAG)**

1. Production, supply, distribution and prices of petroleum and petroleum products.
2. Exploration for and exploitation of oil resources in India including the setting up of participatory projects e.g. Indo-Stanvac Petroleum Project, Oil India Ltd., etc.
3. Setting up of Oil Refineries in India.
4. Production of refinery products by—
 - (i) Standard Vacuum Refinery Company, Bombay ;
 - (ii) Burmah-Shell Refinery, Bombay ;
 - (iii) Caltex Refinery, Visakhapatnam, and
 - (iv) Assam Oil Company Ltd., Digboi.
5. Setting up of lubricating oil plants.
6. Petrochemicals.
7. Industries relating to the production of Non-Cellulosic Synthetic Fibres (Nylon, Terylene, Polyester, Acrylic, etc.).
8. Synthetic Rubber.
9. Plastics, including fabrication of plastics and plastic moulded goods.

10. Setting up of a distribution organisation for the sale of petroleum and petroleum products.

11. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.

12. All attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, Public sector projects falling under the subjects included in this list except such projects as are specifically allotted to any other Department.;

**B. DEPARTMENT OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(RASAYAN AUR URVARAK VIBHAG)**

1. Fertilizers.
2. Drugs and other fine chemicals.
3. Caustic Soda and Soda Ash.
4. Chlorine.
5. Sulphuric Acid.
6. Insecticides (excluding the administration of the Insecticides Act, 1968).
7. Antibiotics.
8. Power Alcohol.
9. Potable Alcohol.
10. Heat Treatment Salts.
11. Dye-stuffs.
12. Organic and Inorganic Heavy Chemicals.
13. Miscellaneous Chemicals i.e. Chemicals not specifically allocated to any other Department.
14. Planning, Development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.
15. All Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
16. Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd.
17. Other Public Sector Projects falling under the subjects included in this list, except such projects as are specifically allotted to any other Department.”.

N. SANJIVA REDDY, President

[No. 74/2/1/78-CF]

B. ROY, Jt. Secy.

